

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2026-पीबीआर/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 08-06-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण क्रमांक 357/अपील/2006-07.

पप्पू पिता श्री परमानन्द
निवासी निहालपुर मुण्डी इंदौर

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1-स्वर्गीय श्रीमती लीलाबाई पति स्व०श्री बसंतराव भागवत(विलोपित)
- 2-श्रीमती सुरेखा पति स्व०मुकेश भागवत्
- 3-श्रीमती पुष्पाबाई पति स्व०शिवाजीराव होल्कर
- 4-श्रीमती जयमाला पति योगेश नजाम
श्रीमती जयश्री पति प्रवीण
श्री सौरभ पिता मुकेश
श्री भैय्यू पिता मुकेश (नाबालिग) तर्फे संरक्षक
माता श्रीमती सुरेखा पति स्व०मुकेश
समस्त निवासी 1315/बी सेक्टर, योजना क्रमांक 71, इंदौर
- 5- अनिल पिता श्री शान्तिप्रिय डोसी
पता निहालपुर मुण्डी जिला इंदौर

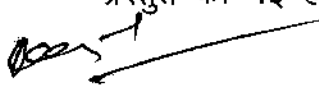
.....अनावेदकगण

.....
श्री लोकेश भार्गव, अभिभाषक-आवेदक
श्री जितेन्द्र पवार, अभिभाषक- अनावेदक क्रमांक 2
श्री एस०के०गंगवाल, अभिभाषक- अनावेदक क्रमांक 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-06-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

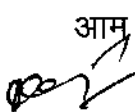




2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा ग्राम निहालपुर मुण्डी तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 689/1/1 पैकि रकबा 1.000 हेक्टेयर पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से 14,00,000/- रुपये में क़य की गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रेतागण लीलाबाई, पुष्पाबाई एवं सुरेखाबाई के स्थान पर उसका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/अ-6/2005-06 दर्ज कर दिनांक 19-10-2006 को आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया कि वर्तमान में विक्रेतागण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज नहीं है और प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में भी विक्रय पत्र निष्पादित हो चुका है, अतः आवेदक का नामान्तरण नहीं किया जा सकता है । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16-07-2007 को आदेश पारित कर उपरोक्त निष्कर्ष के साथ प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16-07-2007 के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 08-06-2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 16-01-1997 को मुन्नालाल पिता मूलचन्द को प्रश्नाधीन सर्वे नम्बर का आम मुख्त्यार नियुक्त किया गया था एवं दिनांक 26-12-1998 को उक्त मुख्त्यारनामा निरस्त कर दिया गया, जिसकी आम सूचना 26-12-1998 को समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी गई । आम





मुख्यार को आम सूचना की जानकारी दिनांक 26-12-1998 को होने पर उसके द्वारा उसी दिन राधेश्याम पिता पन्नालाल के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया और राधेश्याम की मुख्यार आम से मिलीभगत होने के कारण राधेश्याम द्वारा भी उक्त सर्वे नम्बर को कय करने के संबंध में आपत्ति की कोई सूचना किसी समाचार पत्र में नहीं दी गई ।

(2) आम मुख्यार द्वारा राधेश्याम के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है, उसमें सर्वे नम्बर 689 पैके रकबा 1.481 हेक्टेयर लिखा गया है, जबकि आम मुख्यार नामा सर्वे क्रमांक 689 पैके रकबा 1.406 हेक्टेयर का ही मुन्नालाल के पक्ष में जारी किया गया था ।

(3) मुख्यार नामा निरस्त होने की सूचना मुन्नालाल को दी गई थी, इसके बावजूद मुन्नालाल को अधिकार व हक नहीं होने के बाद भी मुन्नालाल द्वारा दिनांक 21-06-1999 को संशोधन पत्र राधेश्याम के पक्ष में निष्पादित करने में अवैधानिकता की गई ।

(4) अनावेदक क्र. 1 लगायत 4 द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 09-01-2002 को विधिवत् प्रश्नाधीन सर्वे नम्बर की रजिस्ट्री निष्पादित की गई है ।

(5) दिनांक 31-03-2006 को राधेश्याम द्वारा मुन्नालाल को फिर से प्रश्नाधीन भूमि का मुख्यार आम नियुक्त किया गया और उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 5 को दिनांक 13-04-2006 को विक्रय कर दी गई । आवेदक का परिवार मृतक बसंतराव के समय से ही उक्त कृषि भूमि पर बटाई के आधार पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है और पटवारी रिपोर्ट में भी आवेदक का कब्जा बताया गया है ।

(6) मुख्यारनामे की वैधता एक वर्ष के लिये होती है और दिनांक 16-01-1997 को निष्पादित मुख्यारनामा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् मुन्नालाल द्वारा रजिस्ट्री निष्पादित की गई है, जो कि प्रारंभ से ही शून्यवत् है ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) आवेदक का परिवार मृतक बसंतराव के समय से ही उक्त भूमि पर बटाई के आधार पर कृषि कार्य करता आ रहा है । दिनांक 18-07-2006 को पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड में भी वादग्रस्त सिंचित भूमि पर आवेदक पप्पू का कब्जा बताया गया है । माह जून, 2007 में आवेदक पप्पू द्वारा फसल बोई गई है और बोरिंग लगवाया गया है ।

(2) कृषि भूमि अनाधिकृत और गैर कानूनी रूप से मुन्नालाल को विक्रय कर दी गई है, जो कि प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है, अतः राधेश्याम द्वारा नियुक्त आम मुख्त्यार द्वारा अनावेदक कमांक 5 के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का किया गया विक्रय भी प्रभावशून्य है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 16-01-1997 को मुन्नालाल पिता मूलचन्द को प्रश्नाधीन सर्वे नम्बर का आम मुख्त्यार नियुक्त किया गया था एवं दिनांक 26-12-1998 को उक्त मुख्त्यारनामा निरस्त कर दिया गया, जिसकी आम सूचना 26-12-1998 को समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी गई । आम मुख्त्यार को आम सूचना की जानकारी दिनांक 26-12-1998 को होने पर उसके द्वारा उसी दिन राधेश्याम पिता पन्नालाल के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया और राधेश्याम की मुख्त्यार आम से मिलीभगत होने के कारण राधेश्याम द्वारा भी उक्त सर्वे नम्बर को कय करने के संबंध में आपत्ति की कोई सूचना किसी समाचार पत्र में नहीं दी गई ।

(4) आम मुख्त्यार द्वारा राधेश्याम के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है, उसमें सर्वे नम्बर 689 पैकि रकबा 1.481 हेक्टेयर लिखा गया है, जबकि आम मुख्त्यार नामा सर्वे कमांक 689 पैकि रकबा 1.406 हेक्टेयर का ही मुन्नालाल के पक्ष में जारी किया गया था ।



(5) मुख्ख्यार नामा निरस्त होने की सूचना मुन्नालाल को दी गई थी, इसके बावजूद मुन्नालाल को अधिकार व हक नहीं होने के बाद भी मुन्नालाल द्वारा दिनांक 21-06-1999 को संशोधन पत्र राधेश्याम के पक्ष में निष्पादित करने में अवैधानिकता की गई ।


(6) अनावेदक क्र. 1 लगायत 4 द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 09-01-2002 को विधिवत् प्रश्नाधीन सर्वे नम्बर की रजिस्ट्री निष्पादित की गई है ।

(7) दिनांक 31-03-2006 को राधेश्याम द्वारा मुन्नालाल को फिर से प्रश्नाधीन भूमि का मुख्ख्यारआम नियुक्त किया गया और उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्र. 5 को दिनांक 13-04-2006 को विक्रय कर दी गई। आवेदक का परिवार मृतक बसंतराव के समय से ही उक्त कृषि भूमि पर बटाई के आधार पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है और पटवारी रिपोर्ट में भी आवेदक का कब्जा बताया गया है ।

(8) मुख्ख्यारनामे की वैधता एक वर्ष के लिये होती है और दिनांक 16-01-1997 को निष्पादित मुख्ख्यारनामा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् मुन्नालाल द्वारा रजिस्ट्री निष्पादित की गई है जो कि प्रारंभ से ही शून्यवत् है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि मुन्नालाल पिता मूलचन्द के हित में निष्पादित आम मुख्ख्यारनामा दिनांक 16-01-1997 दिनांक 26-12-1998 को निरस्त कर दिया गया था, जबकि वास्तविकता यह है कि विक्रय पत्र के पंजीकृत दिनांक को उक्त मुख्ख्यार नामा पूर्णत प्रभावशील था और विक्रय पत्र विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही पंजीकृत हुआ है, ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 को आवेदक के तर्क में विक्रय विलेख निष्पादित करने का अधिकार नहीं था ।




(2) संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों के अनुरूप किसी संपत्ति के संबंध में एक बार विक्रय पत्र पंजीकृत होने के पश्चात् जब तक वह व्यवहार न्यायालय से निरस्त नहीं करा लिया जाता तब तक वह अस्तित्व में रहता है और प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण नहीं किया जा सकता है और यदि अन्तरण कर दिया जाता है तब पश्चातवर्ती अन्तरण शून्य रहता है ।

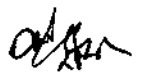
(3) राधेश्याम के पक्ष में दिनांक 26-12-1998 को विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है और अवधि विधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार दिनांक 25-12-2000 तक राधेश्याम के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को चुनौती दी जा सकती थी, परन्तु उसे चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है । इस प्रकार राधेश्याम के मुख्यार आम के द्वारा अनावेदक क्रमांक 5 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र वैधानिक एवं उचित है और आवेदक के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र बोगस व निष्प्रभावी है एवं आवेदक नामान्तरण कराने का अधिकारी नहीं है ।

(4) अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा मुन्नालाल पिता मूलचन्द को आम मुख्यार आम नियुक्त कर मुख्यारनामा पंजीकृत कराया गया है और मुख्यारआम द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया है जिसे अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 चुनौती देने से विबंधित (Stopped) है ।

(5) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों सहित इस निगरानी में मुख्यार नामा निरस्ती के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किये गये हैं, इसलिये अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा मुख्यार नामा निरस्ती के संबंध में किये गये कथन विचार योग्य नहीं है ।

(6) अनावेदक क्रमांक 5 केता द्वारा राधेश्याम से विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक को ही आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है और प्रश्नाधीन भूमि शांतिपूर्ण ढंग से अनावेदक क्रमांक 5 के आधिपत्य में चली आ रही है । राजस्व अभिलेखों में भी बतौर भूमिस्वामी अनावेदक क्रमांक 5 का नाम दर्ज हो गया है, इसलिये आवेदक सहित अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से किये गये कथन त्रुटिपूर्ण है कि प्रश्नाधीन





भूमि पर आवेदक का कब्जा है । तर्क के समर्थन में 2010 (3) एमपीएलजे 625, आईएलआर 2008(एमपी) 1199 एवं 1999 जेएलजे 45 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामियों द्वारा दिनांक 16-01-1997 को प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में मुन्नालाल पिता मूलचन्द के पक्ष में आम मुख्त्यार नामा निष्पादित कर पंजीकृत कराया जाकर मुख्त्यार आम को प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य करने, बटाई पर देने, हिस्सा लेने, सिंचाई करने एवं भूमि को एकसाथ अथवा भागों में विक्रय करने सहित अन्य अधिकार दिये गये और मुख्त्यार आम मुन्नालाल पिता मूलचन्द द्वारा दिनांक 26-12-1998 को सर्वे क्रमांक 689 रकबा 2.177 हेक्टेयर भूमि का विक्रय राधेश्याम पिता पन्नालाल को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से किया गया है एवं प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज भी हो गया है, तत्पश्चात् भूमिस्वामी लीलाबाई, पुष्पाबाई, श्रीमती सुरेखा एवं जयमाला (नाबालिग) संरक्षक माता श्रीमती सुरेखा द्वारा सर्वे क्रमांक 689/1/1 पैकि रकबा 1.000 हेक्टेयर भूमि का विक्रय, विक्रय पत्र दिनांक 09-01-2002 पंजीकृत दिनांक 26-05-2005 से आवेदक को किया गया है और उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से कय की जाने के कारण नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । उक्त आवेदन पत्र को तहसीलदार द्वारा दिनांक 19-10-2006 को आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि विक्रेता का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज नहीं है और प्रश्नाधीन भूमि की पूर्व में रजिस्ट्री हो चुकी है ।

1982 आरएन 218 नगर पालिका श्योपुर विरुद्ध यासीन मोहम्मद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

“संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882-धारा 8-विक्रेता को कोई स्वत्व नहीं-केवल को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते।”




इसी प्रकार 1987 आरएन 408 कृपाशंकर विरुद्ध केदार तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

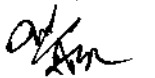
“धारा 109 तथा 110-नामान्तरण नियम-नियम 32-भूमि का दो बार विक्रय-प्रथम क्रेता नामान्तरण का अधिकारी है-विक्रेता को पुनः विक्रय करने का स्वत्व नहीं-द्वितीय क्रेता को कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता है।”

2010 आरएन 355 सुनीलकुमार विरुद्ध डॉ.ओमप्रकाश गर्ग तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :-

“एक ही भूमि का दो विक्रय विलेख विक्रेता को पुनः विक्रय करने का अधिकार नहीं है और ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर पश्चात्कर्ता क्रेता को स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और उसका नामान्तरण कोई प्रभाव नहीं रखता है।”

जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय दिनांक 26-12-1998 को राधेश्याम को किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में विक्रेता को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व नहीं रह गये थे, और उन्हें भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था। अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में द्वितीय क्रेता आवेदक पप्पू को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और तहसीलदार द्वारा पारित आदेश माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में पूर्णतः विधि अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। इस संबंध में आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि जिस दिनांक को मुख्याार आम द्वारा राधेश्याम के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है, उस दिनांक को मुख्याार नामा निरस्त किया जाकर सूचना जारी कर दी गई थी, इसलिये मुख्याार आम को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं रह गया था, क्योंकि आवेदक की ओर से मुख्याारनामा निरस्त कर सूचना दिये जाने का उल्लेख किया जा रहा है, परन्तु किसी भी न्यायालय में पंजीकृत मुख्याार नामा निरस्ती पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इससे परिलक्षित





होता है कि मुख्तारनामा निरस्ती पत्र पंजीकृत नहीं कराया गया है, केवल मुख्तारनामा निरस्ती की सूचना मात्र दी गई है। इस संबंध में एल.एल.आर.(2008) एम.पी.,1199 भीवजी द्वारा वारिसान एवं अन्य विरुद्ध राजेश एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

“रजिस्ट्रेशन अधिनियम (1908 का 16)-धारा 32 (सी)-रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा-यदि मुख्तारनामा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा निष्पादित किया गया हो तो उसके निरसन के लिये रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज ही अपेक्षित है-नोटिस की तामीली द्वारा उसके निरसन की सूचना देना उचित नहीं है।”

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में मुख्तारनामा निरस्त किये जाने संबंधी कथन मान्य योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि पूर्व विक्रय पत्र अवैधानिक है, तब सर्वप्रथम अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 को उसे व्यवहार न्यायालय से निरस्त कराना चाहिये था, तत्पश्चात् भूमि का अन्तरण किया जाना चाहिये था, पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि राधेश्याम द्वारा नियुक्त मुख्तारनामा द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अनावेदक क्र. 5 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया गया है, और अनावेदक क्र. 5 का नाम भी प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त आशय के ही निष्कर्ष निकाले जाकर की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं। 1986 आरएन 23 प्रभुदयाल तथा अन्य विरुद्ध राजस्व मण्डल तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

“धारा 50-पुनरीक्षण शक्तियों की सीमा-तथ्य विषयक समवर्ती निष्कर्ष-बिना ठोस आधार तथा अकाट्य कारणों के हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता-अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार करना आवश्यक है।”





इसी प्रकार 2009 आरएन 285 शोभानाथ तथा अन्य विरुद्ध छत्रधारी में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

“धारा-50 दो निचले न्यायालयों के समरूप निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।”


2012 आरएन 409 गोपीलाला विरुद्ध बंशीलाल तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

“धारा-50 तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।”

अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-06-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर